

इस विश्व पर्यावरण दिवस पर सोनी सब के कलाकारों ने साझा किए दिल से जुड़े संदेश -छोटे प्रयास जो पृथकी पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें हमारी पृथ्वी की रक्षा के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता बढ़ाने से लेकर टिकाऊ जीवनशैली को अपनाने तक, यह दिन हमें एक हरित भविष्य के लिए सार्थक कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर सोनी सब के कलाकार करुणा पांडे, वृहि कोडवारा, परीबा प्रणति और आदित्य रेडिज पर्यावरण के प्रति जागरूकता, व्यक्तिगत इको-फैंडली आदतों और प्रकृति के लिए अपने खास योगदान की बातें साझा कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि किस तरह अर्थ डे को सेलिब्रेट करने

पुष्पा इम्पासबल म पुष्पा
का किरदार निभा रही करुणा
पांडे ने कहा, विश्व पर्यावरण
दिवस का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण,
जलवायु परिवर्तन और
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने
वाले अन्य मुद्दों को लेकर
जागरूकता फैलाना है।
कोविड-19 के बाद हमें यह

महसूस हुआ कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। पृथ्वी को बचाने का सबसे आसान तरीका है — रीड्यूस, रीयूज और रीसाइकल। हमें संसाधनों के उपयोग में टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और इन तीन 'आर' को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संसाधनों और लैंडफिल स्पेस का संरक्षण हो सके। वागले की दुनिया छँ नई पीढ़ी, नए किस्से में वंदना का किरदार निभा रही परीका प्रणति ने कहा, एक मां, एक अभिनेत्री और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरी-भरी और स्वस्थ धरती छोड़नी चाहिए। पर्यावरण दिवस यह याद दिलाने का एक सुंदर अवसर है कि हर छोटा प्रयास मायने रखता है।

मग्न में 105 दिन तक चलेगा संगठन सृजन अभियान



मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे में दिए संगठन मंत्र पर मप्र में काम शुरू हो गया है। एआईसीसी (अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी) की तरफ से नियुक्त किए गए 61 आव्वर्वर और मप्र संगठन के बीच बुधवार को चर्चा हुई। तथा हो गया है कि अगले 105 दिन में जिले से लेकर मोहल्ले तक की कमेटियों को नया स्वरूप दिया जाएगा।

इस प्लान का बड़ा हिस्सा है पैनल, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, सामान्य के साथ कुल 6 नाम अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे। इस काम को 10 जून से 30 जून के बीच और बाकी प्रक्रिया अगले 40 दिन में पूरी करनी होगी।

एआईसीसी के 61 ऑब्जर्वर के साथ हर जिले में 3 ऑब्जर्वर पीसीसी की तरफ से रहेंगे। यह लोग जिलों में जाकर सभी विधायक या सांसद, विधायक प्रत्याशी रहे नेता के साथ वहां के सीनियर नेताओं से फीडबैक लेंगे। लेकिन सबसे ज़रुरी फीडबैक जनता से लिया जाएगा कि उनके लिए कौन व्यक्ति हमेशा मैदान में खड़े

‘नक्शा’ राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

मीडिया ऑफीटर, भोपाल (एजेंसी)।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'नक्शा' वेब जीआईएस प्लेटफॉर्म पर कार्यशाला का शुभारंभ आईआईएसईआर (भौरी), भोपाल में हुआ। कार्यशाला का उद्देश्य भू-प्रबंधन एवं प्रशासनिक प्रणाली को पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाना है। कार्यशाला में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व और नगरीय प्रशासन सचिव, नगर निगम आयुक्त, और 120 से अधिक नगरीय निकायों के 200 से अधिक प्रतिभागियों सहित भू-प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों ने भाग लिया। 'नक्शा' वेब-जीआईएस सॉल्यूशन पर आधारित कार्यशाला में इस प्लेटफॉर्म की क्षमताओं का शहरी संपत्ति सर्वेक्षण और भू-स्थानिक डाटा प्रबंधन में उपयोग पर प्रकाश डाला गया। उद्घाटन सत्र में केन्द्रीय भूमि संसाधन विभाग के निदेशक श्री श्याम कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व श्री विकें पोरवाल, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री संकेत एस. भोंडवे, निदेशक आईआईएसईआर भोपाल प्रो. गोबर्धन दास और परियोजना निदेशक एमपीएसईडीसी श्री गुरु प्रसाद ने संबोधित किया। कार्यशाला के पहले दिन 'नक्शा' प्लेटफॉर्म की विशेषताओं और इसके शहरी संपत्ति सर्वेक्षण में वास्तविक उपयोग के संदर्भ में टेक्निकल प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो प्रस्तुत किये गए। सर्वे ऑफ इंडिया और एमपीएसईडीसी के विशेषज्ञों ने ड्रोन आधारित इमेज एनालिसिस, फीचर एक्सट्रैक्शन और ग्राउंड लेवल सर्वे की विधियों पर परिशिष्ट दिया।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान -2025 के तहत सीएमएचओ कार्यालय सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हुआ पौधारोपण



मीडिया ऑडीटर, भोपाल
 (एजेंसी)। विश्व पर्यावरण
 दिवस पर एक पेड़ मां के नाम
 अभियान के तहत स्वास्थ्य
 संस्थाओं में पौधारोपण किया
 गया। इस अवसर मुख्य
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
 कार्यालय सहित सभी स्वास्थ्य
 संस्थाओं में पौधारोपण कर इनके
 संरक्षण की शपथ ली गई।
 सीएएचओ कार्यालय परिसर
 भोपाल में डॉ. प्रभाकर तिवारी ने
 सिंदूर, आंबला, तुलसी सहित
 त्रिपुष्टि और पर्मिया पौधे लगाए।

स्वास्थ्य संस्करण संस्थानीय नाम
असंतुलन से होने वाले जानकारी तथा बनावट अपै

राष्ट्रगाल पाटेल ने रामाराल का गौधा रोा कर दिया। रायतवरण संरक्षण का संदेश

सीहिया आँहीटर

माडवा आडिटर, मायपाल (एजेंसी)। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजके नवग्रह उद्यान में पौधारोपण किया। उन्होंने रामफल पौधा लगाया। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रदेशवासियों से भलगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उक्त कहा कि हम सभी अपने जीवन के विशेष अवसरों जैसे दिवस, वर्षांगत आदि पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल के अपर सचिव श्री के. सी. गुप्ता ने लीची का पौधा लगाया। सचिव श्री उमाशंकर भार्गव ने सिंट्रूर का पौधा लगाया।

त सीएमएचओ आ गौड़ियारोगा

पानी के समुचित उपयोग के संबंध में उन्मुखीकरण किया गया। जिले के सभी आयुष्मान अपरोग्य मंदिरों में आयोजित कार्यक्रमों में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए निरंतर रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के उपयोग, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, सेहतमंद जीवन शैली अपनाने, ई-वेस्ट को कम करने, कूड़ा कचरा कम करने एवं अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी दी गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं छोटे

कित्सालय में उत्कृष्ट उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करें - संभागायुक्त सिंह

मीडिया ऑडीटर, भोपाल
(एजेंसी)। संभागायुक्त श्री संजीव सिंह
ने कहा है कि पं. खुशीलाल शर्मा
आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं
महाविद्यालय में इलाज कराने आने वाले
मरीजों को सुगमता से अच्छी उपचार
सुविधा मिले यह सुनिश्चित किया जाए।
कम्पोजिट भवन परिसर में सुरक्षा की दृष्टि
से सीसीटीवी कैमरे एवं अन्य समस्त
उपाय किए जाएं। संस्थान के लिए क्रय
किए जाने वाली सामग्री उत्तम गुणवत्ता की
हो तथा शासन के नियमानुसार क्रय की
जाए। संस्थान के भवन उपकरणों के

भोपाल
संग्रहीत सिंह

बैठक में संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि
इन्डोर स्पॉर्ट्स काम्प्लेक्स में क्रय किए
जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो
एवं बेडमिंटन कोर्ट आदि का निर्माण
अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप किया
जाए। प्रयोगशालाओं में आवश्यक
उपकरण एवं पुस्तकालय के लिए पुस्तकों
का क्रय नियमानुसार किया जाए। बैठक
में संस्थान में पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 में
बीएससी नरसिंह पाठ्यक्रम प्रारंभ किए
जाने, संस्थान में कार्यरत अतिथि
प्राध्यापकों, शिक्षक, कर्मचारियों आदि
की वेतनवृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान
किए जाने, संस्थान चिकित्सालय में
दैनिक उपयोग की सामग्रियां क्रय किए
जाने, पी एंड टी विभाग में आडियोमेट्री
मशीन क्रय, लिफ्ट के एनुअल मेटेनेंस,
एक्स रे मशीन की कार्योत्तर स्वीकृति, डीप
फ़ीजर क्रय, आदि के संबंध में प्रस्ताव रखे
गए तथा विवारित किया गया।

विचार

सुपरकंडविटियों के क्षेत्र में रोबर्ट श्राइफर का योगदान

जॉन रॉबर्ट श्रीफ़र, एक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने सुपरकंडक्टिविटी के अग्रणी सिद्धांत को विकसित करने के लिए 1972 के नोबेल पुरस्कार में हिस्सा लिया। रॉबर्ट श्राइफ़र का जन्म 31 मई, 1931, तल्हासी, प्लॉरिडा में हुआ एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और विजेता थे, जॉन बार्डीन और लियोन एन. कूपर के साथ, बिसीएस सिद्धांत सुपरकंडक्टिविटी का पहला सफल सूक्ष्म सिद्धांत विकसित करने के लिए 1972 का नोबेल पुरस्कार जीता। श्राइफ़र ने मैसैचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज और इलिनोइस विश्वविद्यालय, अर्बाना-शैंपेन में शिक्षा प्राप्त की, जहाँ उन्होंने 1957 में पीएचडी प्राप्त की। वह इलिनोइस विश्वविद्यालय में बार्डीन के अधीन काम करने वाले एक युवा स्नातक छात्र थे, जब उन्होंने यह समझाने में मदद की कि धातुएँ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध क्यों खो देती हैं। श्रीफ़र ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो (1957-59) और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस (1959-62) में पढ़ाया, इससे पहले कि वे यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया के संकाय में शामिल हो गए, जहाँ 1964 में उन्हें मैरी अमांड़ा बुढ़ भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया। 1992 में फ्लॉरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में जाने से पहले श्रीफ़र कॉर्नेल यूनिवर्सिटी (1969-75) में एंड्रयू डी. व्हाइट प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सांता बारबरा (1980-91) में भौतिकी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1964 में थ्योरी ऑफ सुपरकंडक्टिविटी प्रकाशित की। अपने सहकर्मियों जॉन बार्डीन और लियोन कूपर के साथ मिलकर, श्रीफ़र को अष्ट्रेसिटी सिद्धांत विकसित करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे अतिचालकता का पहला सफल सूक्ष्म सिद्धांत माना जाता है, जिसमें कुछ सामग्रियों की व्यावहारिक रूप से शून्य प्रतिरोध के साथ विजली का सचालन करने की क्षमता शामिल है।

अमेरिकी भौतिकविदों जॉन बार्डीन, लियोन एन. कूपर और जॉन आर. श्रीफर द्वारा बीसीएस सिद्धांत अतिचालक पदार्थों के व्यवहार को समझाने के लिए विकसित एक व्यापक सिद्धांत है। जब अतिचालक को पूर्ण शून्य के करीब तापमान पर ठंडा किया जाता है, तो वे अचानक विद्युत प्रवाह के प्रवाह के लिए सभी प्रतिरोध खो देते हैं। कूपर ने पाया था कि सुपरकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जोड़े में समूहीकृत होते हैं, जिन्हें अब कूपर जोड़े कहा जाता है, और एक एकल सुपरकंडक्टर के भीतर सभी कूपर जोड़ों की गति सहसंबद्ध होती है; वे एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करते हैं जो एक एकल इकाई के रूप में कार्य करती है। सुपरकंडक्टर पर विद्युत बोल्टेज के अनुपयोग से सभी कूपर जोड़े गति करते हैं, जिससे करंट बनता है। जब बोल्टेज हटा दिया जाता है, तो करंट अनिश्चित काल तक बहता रहता है क्योंकि जोड़े किसी विरोध का सामना नहीं करते हैं। करंट को रोकने के लिए, सभी कूपर जोड़ों को एक ही समय में रोकना होगा, जो एक बहुत ही असंभव घटना है। जैसे ही एक सुपरकंडक्टर गर्म होता है, उसके कूपर जोड़े अलग-अलग इलेक्ट्रॉनों में अलग हो जाते हैं, और सामग्री सामान्य या गैर-सुपरकंडक्टिंग बन जाती है। श्रीफर ने याद किया कि जनवरी 1957 में वे न्यूयॉर्क शहर में एक सबवे पर थे, जब उन्हें गणितीय रूप से सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनों की मूल अवस्था का वर्णन करने का विचार आया। श्रीफर और बार्डीन के सहयोगी कूपर ने पाया था कि सुपरकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जोड़े में समूहीकृत होते हैं, जिन्हें अब कूपर जोड़े कहा जाता है, और यह कि एक एकल सुपरकंडक्टर के भीतर सभी कूपर जोड़ों की गतियाँ सहसंबद्ध होती हैं और फोनॉइ-इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रैक्शन के कारण एक एकल इकाई के रूप में कार्य करती है। श्रीफर की गणितीय सफलता प्रत्येक व्यक्तिगत जोड़े के बजाय एक ही समय में सभी कूपर जोड़ों के व्यवहार का वर्णन करना था। इलिनोइस लौटने के अगले दिन, श्रीफर ने अपने समीकरण बार्डीन को दिखाए, जिन्होंने तुरंत महसूस किया कि वे समस्या का समाधान थे। सुपरकंडक्टिविटी के बी सी एस सिद्धांत (बार्डीन-कूपर-श्रीफर द्वारा की गई खोज), जैसा कि अब जाना जाता है, 30 से अधिक वर्षों के प्रायोगिक परिणामों के लिए जिम्मेदार था जिसने भौतिकी के कुछ महान तम सिद्धांतकारों को रोक दिया था। अतिचालकों के व्यवहार के कई अन्य पहलुओं को बी.सी.एस. सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। सिद्धांत एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा कूपर जोड़ों को उनके व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनों में अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रयोगात्मक रूप से मापा जा सकता है। उनका निधन ओक पार्क, इलिनोइस, यू.एस. में 27 जुलाई, 2019 हो गया है। वह 88 वर्ष के थे उनके परिवार के सदस्यों का कहना है कि श्रीफर की शनिवार 27 जुलाई, 2019 को फ्लोरिडा के तल्हासी में एक निर्सिंग सुविधा में नींद में ही मृत्यु हो गई, जहां वह एक समय फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे सुपरकंडक्टिविटी के इस खोज हेतु वैज्ञानिक कॉर्स क्षेत्र में एक नई दिशा विज्ञान के विकास में मिली इनका बी सी एस सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में आज भी लोग याद करते हैं।

महासचिव पद पर असंवैधानिक नियुक्ति?

संसद की प्रशासनिक रीढ़ उसका सचिवालय और निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 98 में स्पष्ट रूप से लोकसभा और राज्यसभा के लिए स्वतंत्र सचिवालय सेवा की स्थापना, कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रक्रिया और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान संसद को कार्यपालिका से स्वतंत्र बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले दो दशकों से, इस संविधानिक भावना एवं नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। जिसके कारण संविधानिक अधिकारों की रक्षा संभव नहीं हो पा रही है। लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव जैसे सर्वोच्च

स्थान बना। वर्तमान में राजनीतिक कृपा प्राप्त अधिकारियों के कारण क्षीण होती जा रही है। आईएएस या अन्य सेवाओं के अधिकारी कार्यपालिका से सीधे जुड़े होते हैं। संसद के सचिवालय में उनकी नियुक्ति सत्ता के नियंत्रण का द्वारा खोल देती है। वह सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे में काम करते हैं जिसके कारण संसदीय परंपराएं एवं संविधान की मूल भावना धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। संसदों के अधिकार सीमित होते जा रहे हैं। जिस तरह से नियम और कानून संसद में बनाए जा रहे हैं। हो-हल्ले के बीच कानूनों को पास किया जा रहा है संसद के अधिकार सरकार के जिम्मे किये जा रहे हैं। संसदीय

स्तंभ स्वतंत्र और संवैधानिक मर्यादा के अधीन हों।

पिछले एक दशक में सरकार द्वारा बहुमत के आधार पर जिस तरह से संसद की कार्यवाही संचालित की जा रही है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति आंख मूँदकर सरकार की बात को मानकर संसद की कार्यवाही को बहुमत के आधार पर चला रहे हैं। उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय में कार्यपालिका के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में तैनात सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव जैसे पद प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं। जिनकी चाबी सरकार के पास होती है। लोकसभा और राज्यसभा के सत्र कम से कम होते चले जा रहे हैं। सरकार उन्हीं मामलों में चर्चा करती है, जिसमें वह कराना चाहती है। विपक्ष की आवाज पूरी तरह खत्म हो गई है। सांसदों को संसद के अंदर बोलने का मौका नहीं मिलता है। सांसदों को सदन के अन्दर जो बोलने की स्वतंत्रता थी, वह भी खत्म हो चली है। इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जिम्मेदार हैं। जो सरकार की मंशा के अनुसार संसद की कार्यवाही को चला रहे हैं। संसद में सरकार के बिल हो हल्ले के बीच बिना चर्चा के पास हो रहे हैं। जिसके कारण अब संसद का वह महत्व नहीं रहा, जो संविधान ने उसे दिया था। लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति सभी दलों के सांसदों के हितों की रक्षा करने वाला होता है। वह किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पिछले कुछ सालों में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति विपक्ष के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। उससे ऐसा प्रतीत होता है, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का पद भी सरकार के अधीन हो गया है। अन्यथा, क्या कारण है कि जब सांसदों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी विषय में चर्चा कराना चाहते हैं। आसदंडी उनकी प्रश्न और उनकी मांग को ढुकराकर वही निर्णय करती है, जो सरकार चाहती है। संसद के सत्र इतने छोटे क्यों किये जा रहे हैं। अब सांसद स्वतंत्रता के साथ अपनी बात भी सदन के अंदर नहीं रख पाते हैं। सांसदों से संसद में अपनी बात रख पाने के पहले, उनसे प्रमाण मांगा जाता है। अध्यक्ष और सभापति को सांसदों के अधिकारों और संविधान के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई थी। उस पर अब सरकार का दबाव बन गया है। संसद सचिवालय की यह अवहेलना धीरे-धीरे लोकतंत्र को निरर्थक बना देगी। अब यह कहा जाने लगा है, संसद पर सरकार का कब्जा हो गया है? संसद के पदाधिकारी एवं सांसद अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। आम नागरिकों के मौलिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा किस तरह से कर पाएंगे। केन्द्र की तरह अब राज्यों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। जो चिंताजनक है।

पैसिव स्मोकिंग भी बन रही है मौत का कारण

बचपन से ही हम पढ़ते-सुनते आए हैं कि धूम्रपान तथा तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और शरीर में कैंसर तथा कई अन्य बीमारियों को जन्म देते हैं लेकिन यह जानने-समझने के बाद भी जब हम अपने आसपास किशोरवय बच्चों को भी धूम्रपान करते और विभिन्न तंबाकू उत्पादों का सेवन करते देखते हैं तो स्थिति काफी चिंताजनक प्रतीत होती है। दरअसल ऐसे किशोरों के मनोमस्तिष्क में धूम्रपान को लेकर कुछ गलत धारणाएं विद्यमान होती हैं, जैसे धूम्रपान से उनके शरीर में चुस्ती-फुर्ती आती है, उनका मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत रहता है, व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, कब्ज की शिकायत दूर होती है आदि-आदि। तमाम वैज्ञानिक शोधों के बावजूद ऐसे व्यक्ति समझना ही नहीं चाहते कि धूम्रपान करने से उनके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा नहीं होने वाली कि देखते ही देखते वो किसी ऊँचे पर्वत पर छलांग लगा सकें या महाबली हनुमान

की भाँति समुद्र लांघ जाएं। वास्तविकता यही है कि धूप्रपान एक ऐसा धीमा जहर है, जो धीमे-धीमे इसका सेवन करने वाले व्यक्ति का दम घोंटा है धूप्रपान शरीर में धीरे-धीरे प्राणघातक बीमारियों को जन्म देता है और ऐसे व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया तक पहुंचा देने का माध्यम बनता है। तम्बाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है, जो इस वर्ष तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों से भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा करने के उद्देश्य से 'अपील का पर्दाफाश' तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना थीम के साथ मनाया जा रहा है। एक ओर जहाँ विकासशील देशों में धूप्रपान का प्रचलन बढ़ रहा है, वहाँ अमेरिका सरीखे कुछ विकसित देशों में धूप्रपान के प्रचलन में तेजी से गिरावट आई है। 1965 में

अमेरिका की 42 फीसदी आबादी धूप्रपान की आदी थी जबकि 1991 में यह संख्या घटकर 26 फीसदी रह गई और पिछले डेढ़ दशक में तो वहां धूप्रपान करने वालों की संख्या में और भी तेजी से गिरावट आई है। गहराई में जाने पर पता चलता है कि अमेरिका में सिगरेट की खपत में लगातार कमी आने की वजह से अमेरिका की सिगरेट कम्पनियों ने अपने घाटे की पूर्ति के लिए अपने उत्पादों को भारत तथा अन्य विकासशील देशों में खपाने की योजना बनाई और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली। भारत में प्रतिदिन धूप्रपान से मरने वालों की संख्या सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मुकाबले 20 गुना है जबकि एडस से देश में जितनी मौतें 10 वर्ष में होती हैं, उतनी मौतें धूप्रपान की वजह से मात्र एक सप्ताह में ही हो जाती हैं। करीब दस प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जो खुद धूप्रपान नहीं करते लेकिन पैसिव स्मोकिंग के शिकार बनते हैं।

विश्वविद्यालयों में छात्र आंदोलन राष्ट्र की प्रगति के हित में हो

हाल में देखा गया कि कुछ विश्वविद्यालयों में जो छात्र आंदोलन हुए वो रास्ता भटक गए और अकादमिक विकास की बजाय राजनीतिक झगड़ों में तब्दील हो गए। इससे शिक्षा व्यवस्था की छवि खराब होती है और सीखने का समय बर्बाद होता है। ऐसे में आंदोलनरत छात्रों को शांति से बहस और चर्चा करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को सीखने, शोध और राष्ट्रीय विकास के केंद्र होना चाहिए न कि संर्वात्मक उत्थान।

चाहिए, न कि संघर्ष का स्थान।
 भारत एक युवा राष्ट्र है, जिसकी छात्र आबादी बहुत बड़ी है। अगर छात्र अपनी आवाज को समझदारी से इस्तेमाल करें, तो वे समस्याएं हल करा सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक मिशन है जो शिक्षा की गणवत्ता सुधारता है, छात्रों को कुशल बनाता है और वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करता है। इस नीति के तहत अब छात्रों को विषयों का चुनाव, स्किल ट्रेनिंग और डिजिटल लर्निंग के विकल्प मिल रहे हैं। मल्टीपल एंटी-प्रिजिट सिस्टम से शिक्षा में लचीलापन आया है।

एंगजट सिस्टम से शिक्षा में लचालापन आया ह। हमें जॉब क्रिएटर चाहिए, सिर्फ जॉब सीकर नहीं। नेप नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है। जहां तक मातृभाषा में शिक्षा का सवाल है तो इसमें छात्र गहराई से विषय को समझ पाते हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व भी करते हैं। ऐसे में छात्रों को चाहिए कि वे इन परिवर्तनों का लाभ उठाएं और नकारात्मक आंदोलनों में समय बर्बाद करने की बजाय नवाचार और विकास में भाग लें। यहां



यह समझ लें कि अनुशासन का मतलब चुप्पी नहीं होता। छात्र सवाल कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, यहां तक कि विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन सम्मान और जिम्मेदारी के साथ। जान लें कि शिक्षा एक मजबूत राष्ट्र की नींव है। नारेबाजी से नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, गहरी सीख और सच्चाई के साथ खड़े होकर नेता बनते हैं। वर्तमान में भारत को ऐसे छात्र नेताओं की ज़रूरत है जो अपने समूह से अधिक देश की सोचें। ऐसे में विश्वविद्यालयों को भी चाहिए कि वे खुली चर्चा, नियमित मार्गदर्शन और मूल्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दें। आजादी की लड़ाई से लेकर विज्ञान और समाज सुधार तक, छात्रों ने ईमानदारी और दूरदर्शिता के साथ देश को दिशा दी है। हमें वही जोश फिर से लाना चाहिए। छात्र ऐसे भारतीय बनें जो ज्ञान, शांति और प्रगति में विश्वास रखते हों। छात्र आंदोलन ज़रूरी हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मूल्यों, शांति और बेहतर भविष्य की भावना से संचालित होना चाहिए। सूचित, जागरूक और सक्रिय होना अच्छा है, लेकिन इसके साथ-साथ सम्मान, विनप्रता और जिम्मेदारी भी ज़रूरी हैं। अब जरूरत इस बात की है कि विश्वविद्यालय नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास और नेप पर अधिक वर्कशॉप और सत्र आयोजित करें ताकि छात्र अपनी भूमिका बेहतर समझ सकें। अंततः हमारे छात्र हमारे देश का भविष्य हैं। यदि वे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो भारत अधिक मजबूत, बुद्धिमान और एकजुट होगा। ऐसे में आइए हम सब उन्हें प्रेम, मूल्य और दृष्टि से मार्गदर्शन दें।

